रणजीत टाइम्स

इंदौर

शनिवार, 13 जून, 2026

वर्ष 02 | अंक 143 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से की मुलाकात

NEET छूट से लेकर लंबित फंड जारी करने तक उठाए अहम मुद्दे

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET से राज्य के छात्रों को छूट देने, केंद्र से लंबित वित्तीय सहायता जारी करने और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग की मांग प्रमुखता से उठाई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि राज्य के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए NEET से राहत देने पर विचार किया जाए। उनका तर्क था कि स्थानीय शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष प्रावधान आवश्यक हैं।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पास लंबित विभिन्न मदों के फंड शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कई बुनियादी ढांचा और जनकल्याण परियोजनाएं वित्तीय मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं, जिनके लिए केंद्र की सहायता जरूरी है। इसके अलावा शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए केंद्र से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन देते हुए संबंधित मंत्रालयों को प्रस्तावों की समीक्षा करने के निर्देश देने की बात कही। इस मुलाकात को राज्य के विकास और केंद्र-राज्य समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NEET छूट और लंबित फंड का मुद्दा आने वाले समय में राज्य की राजनीति और शिक्षा नीति दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है।

पंजाब चुनाव की तैयारी में कांग्रेस सक्रिय

मीनाक्षी नटराजन, अजय माकन और भजनलाल जाटव को बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष ने पंजाब की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए तीन वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) नियुक्त किया है। कांग्रेस द्वारा जारी आदेश के अनुसार , और को पंजाब का ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये नेता राज्य में पार्टी संगठन, कार्यकर्ताओं की स्थिति, नेतृत्व और चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने राज्य इकाई में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज किया था। बघेल ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पंजाब में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारी कर रही है। ऑब्जर्वरों की नियुक्ति को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति का आकलन कर चुनावी रोडमैप तैयार किया जा सके।

संघ प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव, शताब्दी एक्सप्रेस के कोच का शीशा टूटा

नई दिल्ली/फिरोजाबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख जिस शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, उस ट्रेन पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास पथराव की घटना सामने आई है। पथराव के कारण एक कोच की खिड़की का शीशा टूट गया, जिससे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में मोहन भागवत समेत किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे रवाना किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही (RPF), (GRP) और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पथराव किसने और किन परिस्थितियों में किया, इसकी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि दोषियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि यह सामान्य शरारती घटना थी या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी। संघ प्रमुख की यात्रा के दौरान हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही पथराव के कारणों और जिम्मेदार लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे पूछताछ, CID ने मूल दस्तावेजों पर दिया जोर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच तेज हो गई है। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और सांसद से राज्य की सीआईडी ने करीब छह घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ के निर्देश पर की गई। मामला टीएमसी विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों से जुड़े दस्तावेजों का है। आरोप है कि कुछ दस्तावेजों में विधायकों की जानकारी और सहमति के बिना उनके हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे।

पूछताछ के बाद सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित मूल दस्तावेजों की बरामदगी बेहद जरूरी है। एजेंसी का मानना है कि मूल रिकॉर्ड मिलने के बाद हस्ताक्षरों की सत्यता और कथित फर्जीवाड़े की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी से दस्तावेजों की उत्पत्ति, उनके उपयोग और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल किए। हालांकि टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पार्टी और उसके नेताओं का किसी भी प्रकार की अनियमितता से कोई संबंध नहीं है। यह मामला राज्य की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और टीएमसी पर निशाना साध रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल जांच में पूरा सहयोग करने की बात कह रहा है। अब सीआईडी की अगली कार्रवाई और मूल दस्तावेजों की बरामदगी पर सभी की नजरें टिकी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

खनियांधाना में जनकल्याणकारी शिविर बना उम्मीद की किरण, विधायक प्रीतम लोधी ने बांटे हितलाभ

अतुल जैन

लाडली लक्ष्मी से ट्राईसाइकिल तक दर्जनों को मिला लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाएं' का दिया मंत्र , कल होगा कुकिंग कंपटीशन

खनियांधाना । "शासन की योजनाएं कागजों से निकलकर जब धरातल पर उतरती हैं, तभी असली जनकल्याण होता है।" यह संदेश गुरुवार को खनियांधाना जनपद पंचायत प्रांगण में आयोजित जनकल्याणकारी शिविर में गूंजा। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 5 से 21 जून तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने सैकड़ों हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ दिलाया।

(कौन-कौन रहा मौजूद)

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिछोर एसडीएम ममता शाक्य ने की। मंच पर जनपद पंचायत सीईओ मोगराज मीणा, तहसीलदार, बीएमओ, बीईओ, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, कृषि, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय, पशुपालन एवं खाद्य विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्व-सहायता समूह की महिलाएं एवं ग्रामीणजन भी शिविर में शामिल हुए।

(सेवा का मौका मिले तो पूरी निष्ठा से निभाओ' : विधायक)

अपने उद्बोधन में विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा, "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि सरकार की हर योजना का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यदि हमें जनता की सेवा का अवसर मिला है तो उसे भगवान का प्रसाद समझकर पूरी निष्ठा और खुले मन से निभाना चाहिए।" उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर आवेदन का निराकरण समय-सीमा में हो और हितग्राही को दर-दर भटकना न पड़े।

(किस-किस को मिला लाभ, देखें पूरी सूची) -विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने अपने हाथों से विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं सामग्री वितरित कीः

1. पर्यावरण संरक्षणः - एक बगिया मां के नाम योजनाः ग्राम पंचायत देखा की श्रीमती राजकुमारी जाटव को पौधरोपण हेतु स्वीकृति पत्र।

2. महिला सशक्तिकरणः - लखपति दीदी योजनाः ग्राम पंचायत मुड़िया की संगीता यादव एवं ग्राम कफार की अनीता लोधी को प्रमाण पत्र। - लाडली लक्ष्मी योजनाः 6 नवजात बालिकाओं के परिजनों को 1.18 लाख रुपये की एफडी के प्रमाण पत्र सौंपे।

3. सामाजिक सुरक्षाः - पेंशन योजनाएंः वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के 18 नए हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र। - सहायक उपकरणः 3 दिव्यांग हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एवं 1 दृष्टिबाधित हितग्राही को सफेद छड़ी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त शिविर में आयुष्मान भारत योजना के 22 नए कार्ड बनाए गए। संबल योजना में 11 नए पंजीयन हुए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 14 परिवारों के नाम जोड़े गए। पीएम किसान सम्मान निधि के 9 किसानों की ई-केवाईसी मौके पर पूर्ण कराई गई।

(समस्याओं का हुआ तत्काल निराकरण)

शिविर में 12 विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए। नागरिकों को पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, तीर्थ दर्शन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। राजस्व विभाग ने नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के 17 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। स्वास्थ्य विभाग ने 87 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित कीं।

(आगे क्याः चित्रकला और कुकिंग से जुड़ेगा जनकल्याण)

जनपद सीईओ मोगराज मीणा ने बताया कि जनकल्याण पखवाड़े को रोचक बनाने के लिए रचनात्मक गतिविधियां भी जोड़ी गई हैं। इसी क्रम में आज 12 जून को जनपद सभागार में स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए 'पर्यावरण संरक्षण' थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को 13 जून को पुरस्कृत किया जाएगा। कल 13 जून को स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए 'पारंपरिक व्यंजन एवं मिलेट्स' थीम पर कुकिंग कंपटीशन होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय पोषण को बढ़ावा देना और महिला समूहों की आय का स्रोत विकसित करना है।

(अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश)

एसडीएम ममता शाक्य ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शेष 43 आवेदनों का 7 कार्यदिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। लापरवाही पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कार्यक्रम का संचालन बीएसी दिनेश शर्मा ने किया एवं आभार प्रदर्शन जनपद सीईओ मोगराज मीणा ने माना। समापन 'हर पात्र को उसका हक, यही जनकल्याण का संकल्प' के उद्घोष के साथ हुआ।

विकास सिर्फ बी जे पी नेताओं के घर के पास

राजेंद्र राजपूत

भोपाल। बी जे पी का विकास सिर्फ बी जे पी नेताओं के घर के पास यह कहावत सिद्ध हो रही है भोपाल के ईश्वर नगर में जहां सीवेज लाइन का कार्य चालू किया गया था और उसके बाद कुछ समय बाद लाइनों को वैसे ही खुदाई करके छोड़ दिया गया एवं जगह-जगह गड्ढे बनें हुए हैं जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है जबकि दूसरे ओर जहां बी जे पी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घर के आसपास सड़क निर्माण एवं सीवेज लाइन और चेंबर काम पूरा किया जा चुका है और आम जनता के द्वारा ठेकेदार और पार्षद को कई बार सूचना दी गई लेकिन अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है अगर गंदगी भरे गड्ढे में कोई गिर जाता है और जान माल का नुक़सान होता है या फिर गंदगी के कारण बीमारी फैलती है तो इसकी जबावदारी किसकी होगी नगर निगम की अमृत परियोजना ठेकेदार की या फिर पार्षद की।

रणजीत टाइम्स

पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सरकार की सख्ती, संदिग्ध लेन-देन रोकने के लिए नई लिमिट लागू

90 दिनों तक थोक बिक्री पर रोक, बड़े खरीदारों और अवैध भंडारण पर कड़ी नजर

www.boudhikpratikar.com

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत ईंधन की थोक बिक्री पर 90 दिनों तक रोक लगाने के साथ ही बड़े और संदिग्ध खरीदारों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार का उद्देश्य अवैध भंडारण, कालाबाजारी और ईंधन के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। नई गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों को संदिग्ध ग्राहकों और असामान्य मात्रा में ईंधन खरीदने वालों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रतिदिन खरीद की सीमा भी तय की गई है, ताकि एक ही व्यक्ति या वाहन द्वारा अत्यधिक मात्रा में

ईंधन की खरीद को रोका जा सके।

अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक

सरकार का मानना है कि कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ईंधन का भंडारण कर बाद में ऊंचे दामों पर बेचने की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

पेट्रोल पंपों को दिए गए निर्देश

तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे असामान्य खरीद की जानकारी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। संदिग्ध लेन-देन पाए जाने पर जांच और कार्रवाई की जा सकेगी।

आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर

सरकारी सूत्रों के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं की नियमित जरूरतों को प्रभावित करना नहीं है। रोजमर्रा के उपयोग के लिए पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले वाहन मालिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

सुरक्षा और आपूर्ति व्यवस्था को मिलेगा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ईंधन आपूर्ति श्रृंखला अधिक पारदर्शी बनेगी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपात परिस्थितियों में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार के इस फैसले को पेट्रोलियम क्षेत्र में निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

TMC के 19 सांसदों की अलग गुट बनाने की मांग, स्पीकर को लेटर भेजकर लगाए साइन

ममता बनर्जी के करीबी रहे कई बड़े नाम भी शामिल, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां तृणमूल कांग्रेस ( ) के 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की है। इस पत्र पर सभी 19 सांसदों के हस्ताक्षर भी होने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, इस सूची में पार्टी के कई वरिष्ठ और चर्चित चेहरे शामिल हैं, जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी सहयोगी के रूप में काम किया था।

किन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन प्रमुख नामों का उल्लेख हो रहा है, उनमें शामिल हैं

»» काकोली घोष दस्तीदार
»» सयोनी घोष
»» पूर्व क्रिकेटर और सांसद

इन नामों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है कि क्या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है या यह किसी रणनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा है।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर 19 सांसदों का यह कदम औपचारिक रूप से स्वीकार होता है, तो यह संसद में पार्टी की एकजुटता और नेतृत्व संरचना पर बड़ा असर डाल सकता है। हालांकि अभी तक न तो पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और न ही स्पीकर कार्यालय की तरफ से इस पर कोई निर्णय सार्वजनिक किया गया है।

आगे क्या हो सकता है?

अब सभी की नजरें लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि इस समूह को अलग गुट का दर्जा मिलेगा या नहीं। फिलहाल इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है।

जर्मनी से डील टूटी तो फ्रांस ने भारत से मिलाया हाथ, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर बड़ी साझेदारी की चर्चा

यूरोपीय फ्यूचर फाइटर प्रोजेक्ट में बदलाव के बाद भारत के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी सहयोग की संभावना तेज

यूरोप के बहुचर्चित फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) प्रोजेक्ट को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच अब फ्रांस और भारत के बीच नई डिफेंस साझेदारी की संभावनाएं चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जर्मनी के साथ फ्रांस का संयुक्त फाइटर जेट प्रोजेक्ट बाधाओं और मतभेदों में उलझने के बाद अब फ्रांस अपने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास के लिए नए साझेदारों की तलाश में है। इस बीच भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रालयों के बीच शुरुआती स्तर की बातचीत होने की बात सामने आई है, जिसमें छठी पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट के विकास में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई है।

फ्रांस ( ) पहले जर्मनी ( ) के साथ मिलकर FCAS प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसे यूरोप का सबसे महत्वाकांक्षी डिफेंस एविएशन प्रोजेक्ट माना जाता है। लेकिन तकनीकी नियंत्रण, साझेदारी ढांचे और औद्योगिक हिस्सेदारी को लेकर मतभेदों के चलते इस परियोजना में रुकावटें आई हैं।

भारत के लिए क्यों अहम है यह मौका?

भारत ( ) लंबे समय से अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम और आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में यदि फ्रांस के साथ छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में साझेदारी आगे बढ़ती है, तो यह भारत की एयरोस्पेस क्षमता के लिए बड़ा कदम माना जाएगा।

क्या हो सकता है आगे?

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अभी यह बातचीत शुरुआती चरण में है और किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, अगर यह साझेदारी आगे बढ़ती है तो इसमें शामिल हो सकते हैं—

एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी
AI आधारित कॉम्बैट सिस्टम
अगली पीढ़ी के इंजन और एवियोनिक्स
संयुक्त डिजाइन और उत्पादन

रणनीतिक महत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की साझेदारी भारत को न केवल तकनीकी बढ़त दे सकती है, बल्कि वैश्विक रक्षा उत्पादन हब बनने की दिशा में भी मदद कर सकती है। फिलहाल, यह पूरा मामला शुरुआती बातचीत के स्तर पर है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में इसे एक बड़े संभावित बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित योग की सजीव अनुभूति है सहजयोग

श्रीमद्भगवद्गीता एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश स्वरूप प्रदान किया था। गीता की विशेषता यह है कि यह किसी एक दर्शन, संप्रदाय या विचारधारा तक

सीमित न होकर सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का संदेश देती है। इसका उद्देश्य केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में मानव का कल्याण संभव है। गीता में श्रीकृष्ण ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा से एकत्व प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं, किंतु इन योगों का वास्तविक अर्थ अत्यंत व्यापक एवं गहन है। निष्काम कर्म, निर्विकल्प ज्ञान और अनन्य भक्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए आत्मबोध आवश्यक माना गया है, जबकि परंपरागत मतों के अनुसार आत्मबोध कठिन साधना का परिणाम समझा जाता है। ऐसे में अनेक लोग स्वयं को इस मार्ग के योग्य नहीं मानते।

वर्तमान समय में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा स्थापित सहजयोग ध्यान आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने का एक सहज एवं व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है। आदिशक्ति स्वरूपा श्री माताजी ने कुंडलिनी जागरण के शाश्वत ज्ञान को पुनः स्थापित किया, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिज्ञासु साधक आत्मज्ञान की अनुभूति सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। जो साधक श्रद्धा एवं समर्पण के साथ आत्मसाक्षात्कार की इच्छा व्यक्त करता है, वह इसकी अनुभूति अपने तालु और हथेलियों पर शीतल चैतन्य के रूप में अनुभव कर सकता है। नियमित ध्यान और आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से मनुष्य का चित्त वर्तमान में स्थिर होने लगता है और वह गीता में वर्णित कालातीत, गुणातीत तथा धर्मातीत अवस्था की ओर अग्रसर होता है। परिणामस्वरूप जीवन के अनेक मानसिक एवं भौतिक संताप स्वतः कम होने लगते हैं और साधक साक्षीभाव में स्थित होकर परमात्मा से गहन एकाकारिता स्थापित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार सहजयोग को श्रीकृष्ण द्वारा गीता में वर्णित योगों की जीवंत एवं प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान की इस वैज्ञानिक एवं पूर्णतः निःशुल्क पद्धति की अधिक जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 18002700800 अथवा www.sahajayoga.org.in पर संपर्क करें।

कलेक्टर सड़कों पर, ठेकेदार बेपरवाह

करैरा में हजारों लीटर पेयजल बहा, जल संकट के बीच उजागर हुई लापरवाही

करैरा। एक ओर भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा स्वयं सड़कों पर उतरकर जल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और आमजन को राहत दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर करैरा नगर की एक तस्वीर प्रशासनिक चिंताओं और जमीनी हकीकत के बीच का बड़ा विरोधाभास उजागर कर रही है।

नगर परिषद करैरा के वार्ड क्रमांक 09 स्थित ब्लॉक गली, सीता सेंटर स्कूल के पास जलावर्धन योजना की पाइपलाइन से हो रही पानी की भारी बर्बादी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, जलावर्धन योजना के तहत कार्य कर रही रियान वाटरटैक कंपनी द्वारा पाइपलाइन की खुदाई किए जाने के बाद दो दिनों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। परिणामस्वरूप प्रतिदिन हजारों लीटर पेयजल सड़कों पर बहकर व्यर्थ हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जलावर्धन योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। नगर में अभी तक व्यापक स्तर पर नल कनेक्शन और जल खपत मीटर लगाए जाने का कार्य भी अधूरा पड़ा है। ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत से संचालित योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विडंबना यह है कि एक ओर जिले के अनेक क्षेत्रों में लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई परिवार देर रात तक जागकर और लंबी दूरी तय कर पेयजल की व्यवस्था करने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर करैरा नगर में अमूल्य जल खुलेआम बहकर नालियों और सड़कों में समा रहा है। जनता का कहना है कि जब शासन और प्रशासन जल संरक्षण को लेकर गंभीर हैं तथा "जल बचाओ" अभियान को प्राथमिकता दे रहे हैं, तब संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार एजेंसियों की उदासीनता आमजन के हितों पर सीधा प्रहार है। यदि समय रहते इस प्रकार की लापरवाही पर

अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में जल संकट और अधिक गंभीर रूप धारण कर सकता है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा जल रिसाव को तत्काल बंद कर पेयजल की बर्बादी रोकी जाए।

"जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं"- यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में हर जिम्मेदार नागरिक और संस्था के लिए एक चेतावनी है।

भाजपा सरकार के दबाव एवं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन ख़ारिज करने के विरोध में महू में धरना प्रदर्शन

महू-इंदौर- जिला कांग्रेस प्रवक्ता जुगनू जादवसिंह धनावत ने बताया कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में महू कोतवाली चौक महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन एवं उपवास कार्यक्रम आयोजित किया।

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार एवं निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के दबाव एवं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है। धरना-प्रदर्शन के दौरान संविधान रचियता बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर कार्यकर्ताओं ने हाथ में लेकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कांग्रेसजनों ने कहा कि भारतीय संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर आवाज उठाती रहेगी। एक दिवसीय उपवास में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेश यादव,कैलाशदत्त पांडे, हरिराम चौहान, विजय नौलखा, जुगनू जादवसिंह धनावत,शक्तिसिंह गोयल, विजेंद्रसिंह चौहान, मोहन अग्रवाल, विष्णु मालवीय, पप्पू खान, पुनीत शर्मा,राजकुमार बागड़ी, लियाकत पठान,नरेश जोशी, मुन्नालाल वर्मा, अजय वर्मा, आनंद गोगलिया, मुस्ताक खान, नारायण पटेल, चूड़िहार साहब, कमल कैथवास, ओम पटेल, महेश निनामा, आसाराम बारूड़, प्रवीण पाटिल, प्रीतम वर्मा, प्रेम चौहान, संतोष अग्रवाल, मुकेश दुबे, गोविंद टेलर, धर्मेंद्र चौहान, सुरेंद्र श्रीवास्तव, रवीश जादम,अरुण गुर्जर,शुभम जैन,भैरू गुर्जर,इत्यादि सैकड़ो कांग्रेस जन उपस्थित रहे। साथ ही महात्मा गांधी जी के भजन भी गाए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ए मालिक तेरे बंदे हम।

राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला तो कांग्रेस निकालेगी मार्च, जीतू पटवारी की BJP को चेतावनी

बोले- लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है भाजपा

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला, तो पार्टी बड़े स्तर पर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जवाबदेही से बच रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अभियान चला रही है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं को "नख-दंत विहीन" बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कांग्रेस ने उठाए जवाबदेही के सवाल-पटवारी ने कहा कि जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहती है, लेकिन यदि मुलाकात का समय नहीं दिया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगी।

मार्च निकालने की चेतावनी-कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में पार्टी कार्यकर्ता प्रदेशभर में आंदोलन और मार्च आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी दल विशेष की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा की है।

भाजपा ने आरोपों को बताया राजनीतिक-वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है। भाजपा का दावा है कि सरकार पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है तथा संवैधानिक संस्थाएं पूरी मजबूती से अपना दायित्व निभा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति और गरमा सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस को राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मिलता है या नहीं, और पार्टी अपने अगले कदम के रूप में क्या रणनीति अपनाती है।

दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग

5 मंजिला इमारत में हादसा, 3 लोगों की मौत, कई को बचाया गया

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के Tughlakabad इलाके में शुक्रवार सुबह एक पांच मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग इमारत के भीतर ही फंस गए। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद पूरी इमारत धुएं से भर गई। ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया।

दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बचाव अभियान के दौरान कई लोगों को धुएं और लपटों के बीच से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और घायलों का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के चलते आग लगी हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं तथा इमारत की सुरक्षा और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए।

पंचायती राज से जुड़ी चार पहलें राष्ट्रीय

ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2026 के लिए चयनित

पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित चार पहलों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2026 के लिए चुना गया है। डिजिटल शासन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण व्यापक बनाने में यह ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल बदलाव श्रेणी में पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक मिला है। यह सूचकांक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों के आधार पर देशभर की ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है।

मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के सांगली जिले की कडेपुर ग्राम पंचायत ने स्वर्ण पदक जीता है। जबकि त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की बिजॉय नगर ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर की पहल श्रेणी के अंतर्गत सेवा वितरण के लिए रजत पदक हासिल किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अभिनव उपयोग और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी वितरण दर्शाते हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद नंदुरबार के स्वास्थ्य विभाग को भी उसकी ई-आरोग्य पहल और स्वास्थ्य सेवा सुधार में डिजिटल उपकरणों के उपयोग धामनी के लिए ई-गवर्नेंस में जिला-स्तरीय पहल के लिए स्वर्ण पदक मिला है।

आगामी 1 और 2 जुलाई को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047: एआई-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जनकल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके।

दीपाली रस्तोगी की टिप्पणी से बढ़ी IAS बिरादरी में तल्खी, विवाद बढ़ने पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संभाला मोर्चा

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद, प्रमोटी और डायरेक्ट IAS अधिकारियों के बीच बढ़ी नाराजगी की चर्चा

भोपाल। मध्यप्रदेश की नौकरशाही में इन दिनों एक सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर चर्चा तेज है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी की एक टिप्पणी के बाद IAS अधिकारियों के बीच असंतोष और बहस का माहौल बन गया। मामला बढ़ता देख मुख्य सचिव अनुराग जैन को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले में एक प्रशासनिक पहल की सराहना को लेकर पूर्व केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारी की सोशल मीडिया पोस्ट पर कई अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी थी। इसी दौरान दीपाली रस्तोगी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह किसी एक अधिकारी की नहीं बल्कि पूरी टीम की उपलब्धि है और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। इसके बाद कुछ अधिकारियों ने इसे संबंधित IAS अधिकारी के योगदान को पर्याप्त महत्व न दिए जाने के रूप में देखा। स्क्रीनशॉट और टिप्पणियां विभिन्न प्रशासनिक समूहों में चर्चा का विषय बन गईं। विवाद के बाद प्रमोटी और डायरेक्ट IAS अधिकारियों के बीच पुराने मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं। कुछ अधिकारियों ने इसे केवल एक टिप्पणी का मामला बताया, जबकि कुछ ने इसे प्रशासनिक संवेदनशीलता से जुड़ा विषय माना। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई अधिकारियों ने इस पर असहमति जताई और मामला वरिष्ठ स्तर तक पहुंच गया।

मुख्य सचिव ने किया हस्तक्षेप- सूत्रों के अनुसार विवाद बढ़ने और नौकरशाही में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने स्थिति पर नजर रखी। प्रशासनिक समन्वय

और कार्यसंस्कृति को बनाए रखने के लिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। अनुराग जैन पहले भी विभागों के बीच समन्वय और शिकायतों के समाधान पर जोर देते रहे हैं।

पहले भी उठ चुके हैं ऐसे सवाल- मध्यप्रदेश की नौकरशाही में प्रमोटी और डायरेक्ट IAS अधिकारियों के बीच प्रतिनिधित्व, पदोन्नति और उपलब्धियों के श्रेय को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है। हालांकि अधिकांश मामलों में वरिष्ठ स्तर पर संवाद के जरिए समाधान निकाल लिया जाता है। फिलहाल नजरें आगे की स्थिति पर-प्रशासनिक गलियारों में अब यह चर्चा है कि क्या यह विवाद यहीं थमेगा या फिर सेवा संगठनों और अधिकारियों के बीच आगे भी इस पर विमर्श जारी रहेगा। हालांकि अभी तक किसी पक्ष की ओर से औपचारिक विवाद या शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटनाक्रम ने मध्यप्रदेश की नौकरशाही में आंतरिक संवाद और संवेदनशीलता के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है।

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, चुनावी कानूनी विकल्प अभी भी खुले

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रही Meenakshi Natarajan को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज किया जाता है, तो उसके लिए चुनावी कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेना होगा और चुनाव आयोग के समक्ष भी मामला उठाया जा सकता है। मीनाक्षी नटराजन ने अपने राज्यसभा नामांकन को खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि जिस मामले का हवाला देकर उनका नामांकन निरस्त किया गया, वह ऐसा आपराधिक मामला नहीं था जिसकी जानकारी नामांकन पत्र में देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो। उनके वकील ने अदालत में कहा कि मामले में अभी संज्ञान तक नहीं लिया गया था और केवल नोटिस जारी हुआ था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन खारिज होने जैसे मामलों में अदालत आमतौर पर सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग और चुनावी कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया ही उपयुक्त रास्ता है। गौरतलब है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कथित रूप से एक लंबित मामले की जानकारी न देने के आरोप में खारिज किया गया था। कांग्रेस इस फैसले का लगातार विरोध कर रही है और चुनाव आयोग के समक्ष भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना और मजबूत हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर घिरे दिग्विजय सिंह, इंदौर महापौर ने उठाई अवमानना कार्रवाई की मांग

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विवाद ने पकड़ा तूल, राजनीतिक संग्राम तेज

मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचने के बाद नया राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद Digvijaya Singh की सुप्रीम कोर्ट संबंधी टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर के महापौर ने उनके बयान को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला

कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी Meenakshi Natarajan के नामांकन पत्र निरस्त होने से जुड़ा है। नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गुरुवार को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं होने पर दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे सर्वोच्च न्यायालय पर अनुचित टिप्पणी बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इंदौर महापौर ने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के प्रति इस तरह की टिप्पणी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकती है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए।

वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में उनके प्रत्याशी के साथ अन्याय हुआ है और पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा जहां दिग्विजय सिंह से अपने बयान पर स्पष्टीकरण की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रही है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और इस पूरे विवाद पर आने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर टिकी हैं।

दलित ईसाई और मुस्लिमों को SC आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट तैयार

जल्द केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी

पूर्व CJI केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाले आयोग ने अध्ययन पूरा किया, आरक्षण नीति पर बड़ा फैसला संभव

दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की मांग पर गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश K. G. Balakrishnan की अध्यक्षता वाले इस आयोग की रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को सौंपी जा सकती है। आयोग को यह जांचने की जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना का सामना करने वाले दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इस विषय पर लंबे समय से सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है।

क्या है मौजूदा व्यवस्था?

वर्तमान में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा मुख्य रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े दलित समुदायों को प्राप्त है। ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलित समुदाय इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें SC आरक्षण

का लाभ नहीं मिलता। आयोग ने किन पहलुओं का अध्ययन किया?

आयोग ने विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों, सामाजिक संगठनों के सुझावों, विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया। रिपोर्ट में सामाजिक भेदभाव, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया है।

राजनीतिक और सामाजिक महत्व

यह मुद्दा वर्षों से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। कुछ संगठन और दल दलित ईसाइयों तथा मुस्लिमों को SC आरक्षण देने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य का तर्क है कि इससे मौजूदा अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

केंद्र सरकार के फैसले पर नजर

अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार इसकी सिफारिशों का अध्ययन करेगी और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। यदि इस विषय में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव होता है तो इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव देशभर में देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू हो सकती है।

केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के दो राज्यों असम और नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए इन दोनों राज्यों की सरकारों के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस सहमति पत्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और विकसित पूर्वोत्तर के सपने को साकार करने में एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्वोत्तर को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है।

उन्होंने सहमति पत्र को सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि यह दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए, श्री शाह ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के विकास की कुंजी है और यह पहल भविष्य में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।

तस्करी और घुसपैठ रोकने पर भारत-बांग्लादेश की बड़ी पहल, सीमा सुरक्षा को लेकर अहम सहमति

नई दिल्ली में BSF-BGB की 57वीं डीजी स्तरीय बैठक संपन्न, ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी पर सख्ती का फैसला भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। नई दिल्ली में आयोजित सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 57वीं महानिदेशक (DG) स्तरीय बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती ड्रग्स तस्करी, हथियारों की अवैध आवाजाही, मानव तस्करी, पशु तस्करी और अवैध घुसपैठ जैसे मामलों पर विशेष चिंता व्यक्त की गई। दोनों पक्षों ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

संयुक्त गश्त और खुफिया साझेदारी पर जोर

बैठक के दौरान सीमा क्षेत्रों में संयुक्त गश्त बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों में निगरानी मजबूत करने और रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति बनी। अधिकारियों का मानना है कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय से सीमा पार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता- भारत और बांग्लादेश ने सीमा क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने यह भी माना कि सीमा पार अपराध केवल सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देते हैं, इसलिए इनके खिलाफ साझा रणनीति आवश्यक है।

द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बल-विशेषज्ञों का मानना है कि BSF और BGB के बीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद से न केवल सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में भी विश्वास और सहयोग का दायरा बढ़ेगा। बैठक के निष्कर्षों को सीमा प्रबंधन और सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हाट के जाम में 'कैद' हुई जिंदगी

एंबुलेंस में तड़पते रहे मरीज,खनियांधाना का शुक्रवार बना 'काल'

अतुल जैन

सभागार मैदान सूना, मौत के मुहाने पर खड़ा मेंन रोड
नियमों को रौंदकर सड़क पर सजा बाजार, प्रशासन बना मूकदर्शक
अगला नंबर किसका?

खनियांधाना। नगर परिषद खनियांधाना क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार को लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार अब आम नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर बस स्टैंड, मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हालात इतने खराब रहे कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने जा रही एंबुलेंसें भी घंटों तक जाम में फंसी रहीं। इससे न केवल मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की आपातकालीन व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार सुबह से ही हाट बाजार में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए खनियांधाना पहुंचे थे। वहीं फल, सब्जी और अन्य सामान बेचने वाले विक्रेताओं ने बस स्टैंड और मुख्य मार्ग के दोनों ओर सड़क पर ही दुकानें सजा लीं। सड़क के किनारे और बीच तक फैली दुकानों के कारण मार्ग संकरा हो गया, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित होने लगा। देखते ही देखते मुख्य सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और पूरा क्षेत्र जाम की चपेट में आ गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार के संचालन के लिए सभागार मैदान निर्धारित किया गया है। परिषद द्वारा समय-समय पर व्यापारियों को मैदान में ही दुकान लगाने के निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश दुकानदार ग्राहकों की अधिक आवाजाही और बेहतर बिक्री के लालच में मुख्य सड़क और बस स्टैंड क्षेत्र में ही दुकानें लगा लेते हैं। इसके कारण हर सप्ताह यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

शुक्रवार को लगे जाम के दौरान सबसे चिंताजनक स्थिति तब बनी जब मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंसें भी जाम में फंस गईं। सड़क के दोनों ओर दुकानों का कब्जा और बीच में खड़े वाहनों के कारण एंबुलेंस को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल सकी।

कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने स्वयं आगे आकर दुकानदारों और वाहन चालकों को हटाकर रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन अव्यवस्था इतनी अधिक थी कि एंबुलेंस को निकलने में काफी समय लग गया। लोगों का कहना है कि यदि किसी गंभीर मरीज की स्थिति नाजुक होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था।

नगर के व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में नगर परिषद द्वारा सड़क पर लगने वाली दुकानों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया गया था। उस समय कुछ दिनों तक यातायात व्यवस्था सुचारू रही, लेकिन प्रशासनिक सख्ती कम होते ही फिर से सड़क पर दुकानें लगने लगीं और पुरानी स्थिति वापस लौट आई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बस स्टैंड क्षेत्र पहले से ही नगर का सबसे व्यस्त इलाका है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क पर दुकानों का लगना और वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग जाम की सबसे बड़ी वजह बन रही है। नागरिकों ने मांग की है कि शुक्रवार के दिन हाट बाजार को पूरी तरह सभागार मैदान में स्थानांतरित कराया जाए तथा मुख्य मार्ग और बस स्टैंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए।

लोगों ने यह भी मांग उठाई है कि नगर परिषद और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाए। साथ ही शुक्रवार को विशेष यातायात व्यवस्था लागू करते हुए बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की जाए, ताकि एंबुलेंस, स्कूल वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बिना बाधा के रास्ता मिल सके। नगरवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। फिलहाल शुक्रवार को लगे भीषण जाम ने नगर की यातायात व्यवस्था और हाट बाजार प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है तथा लोगों को घंटों परेशानी झेलने पर मजबूर कर दिया।

श्रीमद्भागवत कथा में सम्मिलित होकर कथा श्रवण किया

विधानसभा 05 वार्ड क्रमांक 50 के श्री मंगल नगर बिचौली मरदाना स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में सम्मिलित होकर कथा श्रवण किया। इस दौरान व्यासपीठ का विधिवत पूजन कर पूज्य कथा वाचक महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पूज्य प्रेममूर्ति पंडित श्री अभिषेकानंद जी महाराज का स्नेहिल सान्निध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आयोजनकर्ता मंदिर समिति सदस्य गणों एवं रहवासी परिवार उपस्थित रहे I भक्ति, सेवा और सनातन संस्कृति के संवर्धन हेतु इस दिव्य आयोजन के लिए समस्त श्री मंगल नगर परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

दो माह में मंजूर 400 नक्शों की जांच शुरू

इंदौर नगर निगम ने पिछले दो महीनों में स्वीकृत किए गए करीब 400 भवन नक्शों की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं और शिकायतों के सामने आने के बाद की जा रही है। निगम प्रशासन डीएंड (डिजाइन एंड अप्रूवल) व्यवस्था के तहत मंजूर किए गए प्रकरणों की गहन समीक्षा कर रहा है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि नक्शों की स्वीकृति निर्धारित नियमों और भवन उपविधियों के अनुरूप दी गई या नहीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कुछ मामलों में नियमों की अनदेखी कर नक्शों को मंजूरी दी गई।

निजी इंजीनियरों की भूमिका की भी होगी जांच-निगम ने नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया से जुड़े निजी इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया है। अधिकारियों का मानना है कि यदि किसी स्तर पर गलत जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

रिकॉर्ड खंगाल रही निगम टीम-जांच के लिए गठित टीम स्वीकृत नक्शों, तकनीकी रिपोर्टों और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर मौके पर निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि स्वीकृत नक्शों और वास्तविक निर्माण के बीच अंतर का पता

लगाया जा सके।

अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई-नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जांच में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी, नियमों का उल्लंघन या गलत स्वीकृति सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों, इंजीनियरों और जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता बढ़ाने की कवायद-निगम प्रशासन का कहना है कि यह कदम भवन अनुमति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इंदौर में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों के बीच निगम की इस पहल को भवन अनुमति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।